Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 3, May-2018, ISSN 2230-7540

भारत में कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव

Dr. Nitin Bhardwaj*

Lecturer (Economics), S.L. Education Institute, Moradabad

सार – ***इस स्तर पर भारतीय खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक ज्वलंत मुद्दा है दुनिया के सबसे बड़े निजी उद्योगों में से एक है और भारतीय रिटेल उद्योग विशाल विकास क्षमता वाले उभरते क्षेत्रों में से एक है। भारतीय निवेश आयोग के अनुसार, 2015 तक खुदरा क्षेत्र अपने वर्तमान स्तर के 660 अरब डॉलर तक लगभग तीन गुना बढ़ने की उम्मीद है। एफडीआई में उदारीकरण ने खुदरा उद्योग में बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया है। खुदरा उद्योग में एफडीआई का लाभ इसके लागत कारकों को बढ़ाता है। यह देश के उत्पाद या सेवा को वैश्विक बाजार में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। लगभग 12 मिलियन रिटेल आउटलेट्स पैन इंडिया और लगभग 450 बिलियन डॉलर के अनुमानित आकार के साथ, रिटेल सेक्टर शायद भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक है। इस प्रकार एक तथ्य के रूप में एफडीआई को न केवल अनुमति दी जानी चाहिए बल्कि काफी प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, अध्ययन एफडीआई के प्रभाव और खुदरा क्षेत्र में इसकी आवश्यकता और महत्व का पता लगाने की कोशिश करता है और कृषि विपणन में एफडीआई के कुछ संभावित प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है।***

कुंजीशब्द एफडीआई, उदारीकरण, खुदरा बिक्री, कृषि विपणन।

----------X----------

प्रस्तावना

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अप्रैल, 2000 से जनवरी 2015 तक कृषि क्षेत्र में एफडीआई की आमद ने भारत में रोजगार सृजन के माध्यम से निरंतर आर्थिक विकास और विकास प्राप्त किया। एफडीआई का अनुमान है कि ग्रामीण आबादी पर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, भारत के लगभग 600,000 छोटे गांवों में रहते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो विकास और स्थिरता विकास को निर्धारित करता है और भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेवा क्षेत्र, निर्माण विकास, दूरसंचार, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र आदि अन्य क्षेत्र थे, जिन पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों (FDI) द्वारा ध्यान दिया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों की रुचि थी, वास्तव में पूरी तरह से खराब रही है। अध्ययन से पता चलता है कि 2000-2015 की अवधि के दौरान भारत में एफडीआई प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ मुद्दे हैं जो भारत में एफडीआई के प्रवाह को सीमित कर रहे हैं लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। यह माना जाता है कि आगामी वर्ष में कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हो जाएगा। भारतीय कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से रोजगार और विकास के अवसर बढ़े हैं। इसलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में एफडीआई और कृषि क्षेत्र के बीच लंबे समय तक संबंध है।

भारत में, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 19% हिस्सा है। कृषि क्षेत्र ने औसतन ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2011) की 4.1% की वृद्धि दर और 2012 और 2013 में क्रमशः 1.4% और 4.7% की वृद्धि की है। सरकार ने कृषि में 4% की वृद्धि दर को बनाए रखने की उम्मीद दिखाते हुए, अब एक दूसरी हरित क्रांति प्रस्तावित की है। कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकीय उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि को वैश्विक स्तर पर अधिक उत्पादक और लाभदायक बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं के आधुनिकीकरण के साथ-साथ नई सुविधाओं को स्थापित करने के लिए निवेश पर जोर दिया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा है क्योंकि यह ग्रामीण भारत की रीढ़ है जो कुल भारतीय आबादी का 70% से अधिक निवासियों का है। भारत में अधिकांश ग्रामीण आबादी रोजगार और आजीविका के लिए कृषि क्षेत्रों पर निर्भर करती है। भारत में कृषि उद्योग एक महान गति से विकसित हुआ है और निकट भविष्य में कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। वैश्वीकरण के बाद एशिया में हर देश कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का

www.ignited.in

स्वागत करता है और यह अपनी सीमा को लगातार बढ़ा रहा है। भारत एक अपवाद नहीं है, अन्य सभी देशों की तरह भारत ने भी कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति दी। एफडीआई आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सतत विकास, तकनीकी हस्तांतरण को गति देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आर्थिक विकास में वृद्धि गरीबी को कम करती है और जीवन स्तर को उभारती है। (सुरजना, 2014)। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि भूमि (179.9 मिलियन हेक्टेयर) रखती है (आईबीईएफ, 2014) कृषि मंत्रालय, ग्रामीण बुनियादी सुविधा मंत्रालय, और भारत के योजना आयोग कर रहे हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र में किसी भी एफडीआई ध् एनआरआई ध् ओसीबी की अनुमति नहीं है। केवल चाय क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है, जिसमें चाय की संपत्ति भी शामिल है। इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी चाहिए। कृषि उत्पादकता में सुधार और इसे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के साथ समेकित करने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह को बढ़ावा देने की एक मजबूत आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मेजबान देश के कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाता है और सतत विकास, रोजगार, आय और बचत में वृद्धि की ओर जाता है। यह क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, पूंजी और प्रबंधकीय कौशल भी प्रदान करता है। वर्तमान अध्ययन में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और कृषि का विश्लेषण किया गया है।

एफडीआई को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, देश के तकनीकी स्तर को बढ़ाने और विकासशील देशों में नए रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिखाया गया है। यह भी दिखाया गया है कि एफडीआई विकासशील देशों को वैश्विक बाजार में एकीकृत करने और निवेश के लिए उपलब्ध पूंजी को बढ़ाने के साधन के रूप में काम करता है, इस प्रकार गरीबी को कम करने और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। विश्व बैंक विकास रिपोर्ट के अनुसार, 2000 में 1.1 बिलियन से अधिक लोग प्रति दिन 1 अमेरिकी डॉलर से कम और लगभग 2.1 बिलियन लोग यूएस $ 2 से कम पर थे, जिनमें से दो तिहाई से तीन-चैथाई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इस प्रकार, यदि गरीबी पर युद्ध जीता जाना है, तो विकासशील देशों को कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है, जहां गरीबी की घटना सबसे अधिक है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य पड़ाव है क्योंकि यह ग्रामीण भारत की रीढ़ है, जो कुल भारतीय जनसंख्या का 70% से अधिक निवासियों का है। भारतीय अर्थव्यवस्था को उस सेवा क्षेत्र की ओर भारी किया गया है जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 56% योगदान देता है। पिछले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि में सेवा क्षेत्र का योगदान 63.9% रहा है। सेवाओं से उच्च योगदान होना एक विशेषता है जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता है। चीन में, विनिर्माण जीडीपी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए खाता है, जबकि भारत में, विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का 23.1% योगदान देता है। भारत को हमारे कृषि क्षेत्र में 8 से 10% आर्थिक विकास दर से बढ़ना है। ऐसा होने के लिए हमारे कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है जिस तरह से कृषि उपज की खरीद, भंडारण और विपणन के लिए आपूर्ति और वितरण श्रृंखला में भारी निवेश के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए। आपूर्ति और वितरण श्रृंखला जहां किसान तय करता है कि किसको बेचना है और किस कीमत पर। सरकार हमेशा छत की कीमत तय कर सकती है। साथ ही, भारत को अपने खुदरा क्षेत्र को विदेशी पूंजी और प्रतिस्पर्धा के लिए खोलना चाहिए। विदेशी खुदरा विक्रेता आपूर्ति और वितरण श्रृंखला में सर्वोत्तम प्रथाओं और निवेशों को अपने साथ लाएंगे और साथ ही भारतीय कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों के लिए संपर्क खोलेंगे। आधुनिक खुदरा विक्रेता थोक में खरीद करते हैं और कम कीमतों पर बेचते हैं।

वे आपूर्ति श्रृंखला में अक्षमताओं को कम करने और उपभोक्ताओं के लिए लागत में काफी कमी लाने और किसान के लिए बेहतर सौदा हासिल करने पर जोर देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले दो दशकों में तेजी से बदलती जनसांख्यिकी, जीवन शैली और घरेलू उपभोग और उपभोक्तावाद में वृद्धि के साथ विकास के पथ पर रही है। भारत में खुदरा उद्योग तेज गति से बढ़ रहा है और निकट भविष्य में कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। वैश्वीकरण के बाद के युग में, खुदरा व्यापार में एफडीआई विभिन्न देशों में लगातार बढ़ रहा है, भारत अपवाद नहीं है। हालांकि संगठित भारतीय कृषि क्षेत्र में खुदरा बिक्री निष्कर्ष अपने के चरणों में अब भी है। सरकार आर्थिक नीति में परिवर्तन के साथ भारतीय खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के विचार खोल रहा है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में इसने निवेश माहौल को बढ़ावा दिया है और इसकी आर्थिक स्थितियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भारत में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलू जिनका कृषि मशीनरी पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

1. 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ने बागवानी, फूलों की खेती, बीजों के विकास, पशुपालन, मछलीपालन, जल संवर्धन, सब्जियों की खेती, मशरूम और कृषि से जुड़ी सेवाओं और इससे जुड़े क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के माध्यम से अनुमति दी।

2. 2007-08 के लिए फार्म क्रेडिट बनाने के लिए निर्धारित लक्ष्य रु 225,000 करोड़।

3. किसानों को सीधे सब्सिडी देने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

4. कृषि बीमा संस्थानों और नाबार्ड के माध्यम से ऋण सुविधा को भी बढ़ाया गया है।

5. ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का कॉर्पस उठाया जाए।

6. 1000 से अधिक आबादी वाले 66,800 बस्तियों को सभी मौसम सड़कों के साथ जोड़ा जाना है।

7. 1,46,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।

8. रुपये की धुन के लिए निवेश। ष्भारत निर्माणष् के तहत 1,74,000 करोड़ रुपये की परिकल्पना की गई ।

साहित्य की समीक्षा

एफडीआई को भारत की तरह विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है, क्योंकि इसमें नवीनतम तकनीक लाने और अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की उम्मीद की जाती है। वर्तमान अध्ययन की आवश्यकता को उचित ठहराने के लिए, निम्नलिखित साहित्य नीचे दिया गया है।

बुर्फिशर एट अल (1992) ने मेक्सिको में एफडीआई के प्रभाव का विश्लेषण किया और उन्होंने खुलासा किया कि कृषि उत्पादन में 8% की वृद्धि हुई है और इससे उत्पादन की मांग में और वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उचित तंत्र के माध्यम से एफडीआई दृष्टिकोण ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम कर सकता है।

हारून (1999) एफडीआई का न केवल पूंजी के स्रोत के रूप में एक देश के विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव है, बल्कि प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे के हस्तांतरण, उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के माध्यम से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है।

UNCTAD (2009) के अनुसार थ्क्प् में रोजगार उत्पन्न करने, उत्पादकता बढ़ाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निर्यात बढ़ाने और दुनिया के विकासशील देशों के दीर्घकालिक आर्थिक विकास को जारी रखने की क्षमता है।

हुडा (2011) एफडीआई और भारतीय अर्थव्यवस्था ने निष्कर्ष निकाला कि एफडीआई देश की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एक आधार प्रदान करके भारत की वित्तीय स्थिति को बढ़ाता है। अध्ययन की खोज से पता चलता है कि, एफडीआई आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, देश के तकनीकी स्तर को बढ़ाने और विकासशील देशों में नए रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सिंह और वालिया (2015) ने जांच की कि कृषि उत्पादकता और इसे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के साथ सुव्यवस्थित करती है, इसके लिए कई उपायों को अपनाने की मजबूत आवश्यकता है, जिनमें से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। अध्ययन की खोज, कृषि क्षेत्र में एफडीआई की भूमिका और अर्थव्यवस्था की समग्र प्रगति को समझें।

रईस अहमद (2009) ने "डब्ल्यूटीओ और भारतीय कृषि" नामक अपनी संपादित पुस्तक में भारतीय कृषि के बहु-आयामी आयामों और डब्ल्यूटीओ के साथ हमारे संबंधों और भारत और डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्य देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से एफडीआई के प्रभाव से संबंधित है। उरुग्वे दौर समझौते के साथ शुरू होने वाले और वर्तमान दिन तक विस्तारित डब्ल्यूटीओ नियमों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को उनके प्रतिष्ठित कार्यों में बहुत स्पष्ट रूप से लाया गया है। इसने बड़ी स्पष्टता के साथ, कृषि निर्यात के विभिन्न निहितार्थों और किसानों की भलाई के लिए आयात के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी समग्र रूप से पेश किया।

एम शंकर रेड्डी, एम रमेश और एम चंद्राय (2009) ने अपने काम में इस बात को रेखांकित किया है कि डब्ल्यूटीओ सभी का सबसे गहरा भोग प्राप्त कर रहा है, क्योंकि यह विशेष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि के प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन के बढ़ते प्रभाव के साथ एक बड़ी चिंता यह है कि भारतीय कृषि पर छोटे और सीमांत किसान जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर बहुत अधिक निर्भर हैं, छोटे विपणन योग्य अधिशेष हैं और एक सब्सिडी वाली कृषि में प्रतिस्पर्धी होने के लिए भारी बाधाओं के तहत काम करते हैं। उत्पादन और व्यापार शासन, विश्व व्यापार संगठन से लाभ उठा सकता है। यह चिंता अक्सर दूसरी तरफ बढ़ जाती है कि डब्ल्यूटीओ का फैलाव कम टैरिफ शासन के साथ फैल रहा है और रियायती कृषि से उत्पादों के लिए इंडियन मार्केट तक पहुंच बढ़ गई है, जिससे अधिकांश भारतीय किसानों की कृषि आधारित आजीविका को गंभीर नुकसान हो सकता है। नीति निर्माताओं के लिए चुनौती यह है कि भारतीय कृषि को आसन्न डब्ल्यूटीओ के खतरे से कैसे बचाया जाए, भारतीय खेती की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए और किसानों की आजीविका सुरक्षा

को बेहतर बनाने और सुनिश्चित करने के लिए खेती को एक व्यवहार्य और आत्मनिर्भर उद्यम बनाया जाए। इस चुनौती को संबोधित करने की रणनीति में आवश्यक रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) में बाजार से जुड़े गतिशीलता का पुनरू उन्मुखीकरण और इंजेक्शन शामिल होना चाहिए, संसाधन गरीब किसानों की सेवा के लिए सहायक संस्थानों को मजबूत करना, और उचित नीतियों और प्रशिक्षित मानव के साथ बदलाव को तेज करना। वेयर।

पी अरुणाचलम (2009) ने अपने शोधपत्र में कहा है कि पिछले दो दशकों से कृषि ने राजनेताओं, नौकरशाहों, शिक्षाविदों, व्यवसायिकों, आलोचकों और विश्व व्यापार संगठन में बहुत ध्यान आकर्षित किया है? उनके अनुसार सरल कारण यह है कि यह विश्व स्तर पर एकमात्र संगठन है जहाँ आप विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। उनका तर्क है कि कृषि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विकृति का मूल कारण कई वर्षों में औद्योगिक देशों द्वारा अपने कृषि क्षेत्र को दी गई भारी घरेलू सब्सिडी है। इससे बदले में अत्यधिक उत्पादन हुआ और यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डंपिंग के साथ-साथ विकासशील देशों के कृषि उत्पादों को अपने घरेलू बाजारों से बाहर रखने के लिए आयात प्रतिबंध लगाता है। इसलिए, एक उचित कृषि व्यापार शासन की स्थापना के लिए शुरुआती बिंदु औद्योगिक देशों द्वारा दी जाने वाली घरेलू उत्पादन सब्सिडी में कमी, रियायती निर्यात की मात्रा में कमी और कृषि के लिए न्यूनतम बाजार पहुंच के अवसर पैदा करना है। उनका सुझाव है कि इस दौर को फिर से शुरू करने के लिए भारत का विशिष्ट महत्वपूर्ण योगदान है। यह कृषि पर कुछ और लचीलापन दिखाना है लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भारत की विशाल कृषि निर्वाह अर्थव्यवस्था को खोलने की सीमा तक नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से जहां आप कुछ कठिन कमोडिटी क्षेत्रों सहित अन्य सीमित लेकिन वास्तविक बाजार पहुंच की अनुमति दे सकते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

- भारतीय कृषि पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर चर्चा करना।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में एफडीआई और कृषि क्षेत्र का विश्लेषण करना।

वर्तमान क्षेत्र (वर्तमान विपणन) में वर्तमान परिदृश्य

भारत में, कृषि क्षेत्र अत्यधिक असंगठित और खंडित है। छोटे और सीमांत किसानों को ग्रामीण ऋण सुविधा की कमी, इनपुट और फसल की कीमत में निरंतर वृद्धि और बीज की कम गुणवत्ता आदि के कारण भारतीय किसानों और उनकी लाभ संभावनाओं की स्थिति में काफी गिरावट आ रही है, यदि उत्पादन अच्छा है। उसके बाद एक चमक होती है और कीमतें गिर जाती हैं, और अगर फसल खराब होती है, तो किसानों को शायद ही उच्च कीमतों के रूप में कोई मुआवजा मिलता है। यहां किसानों की लाभप्रदता धीरे-धीरे कम हो रही है, जिसने उन्हें शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित करने और बसने के लिए प्रेरित किया, जहां जीवन निर्वाह और भी कठिन है। अध्ययन बीकेटी क्षेत्र के 5 गांवों को कवर करने वाले सूक्ष्म स्तर के सर्वेक्षण पर आधारित है जो 2010-11 में 400 किसानों को कवर करते हुए अब उत्तर प्रदेश, भारत के बाहरी इलाके में स्थित है।

वर्तमान सेट की सीमाएँ

- इन्फ्रास्ट्रक्चर - खुदरा श्रृंखला के लॉजिस्टिक्स में निवेश की कमी रही है, जिससे अर्थव्यवस्था में एक अक्षम बाजार तंत्र बन गया है। हालांकि भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है (लगभग 180 मिलियन मीट्रिक टनध्वर्ष), इसमें एवरी सीमित एकीकृत कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें केवल 5386 स्टैंड-अलोन कोल्ड स्टोरेज हैं जिनकी कुल क्षमता 23.6 मिलियन मीट्रिक टन है, जहाँ लगभग 80% केवल आलू के लिए उपयोग किया जाता है श्रृंखला अत्यधिक खंडित है और इसलिए, विनाशकारी बागवानी वस्तुओं को विदेशी बाजारों सहित दूर के बाजारों से जोड़ना मुश्किल होता है, वर्ष भर निर्बाध आपूर्ति प्रदान करने और संकट की बिक्री को रोकने के लिए उत्पादन अवधियों से शेष वर्ष तक कृषि उपज को ले जाने के लिए भंडारण बुनियादी ढांचा आवश्यक है। पर्याप्त भंडारण सुविधा, परिवहन सुविधा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि की कमी से किसानों को अपव्यय के साथ-साथ बिक्री मूल्य कम करने में भारी नुकसान होता है। हालांकि रिटेलिंग में एफडीआई की अनुपस्थिति में, स्वचालित मार्ग से, 100% की सीमा तक कोल्ड-चेन में एफडीआई की अनुमति है, लेकिन कृषि खुदरा बिक्री के लिए एफडीआई का प्रवाह लगभग कोई भी नहीं है।
- मूल्य श्रृंखला में बिचैलियों का प्रभुत्व बिचैलियों अक्सर बाजार के मानदंडों की धज्जियां उड़ाते हैं और उनके मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता का भी अभाव होता है। राज्य एपीएमसी अधिनियमों द्वारा शासित थोक विनियमित बाजारों ने एक एकाधिकारवादी और निरंकुश चरित्र विकसित किया है। भारतीय किसानों को अंतिम उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कुल कीमत का केवल 1/3 तक प्राप्त होता है, जबकि

संगठित खुदरा क्षेत्र में उच्चतर हिस्सेदारी वाले किसानों द्वारा 2/3तक के मुकाबले। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह बिचैलियों की इस लंबी श्रृंखला से भारतीय किसान का शोषण हुआ है, जो उनकी वर्तमान स्थिति का एक मुख्य कारण है।

- अनुचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सार्वजनिक खरीद और पीडीएस सेट अप और खाद्य सब्सिडी पर बिल की प्रभावशीलता पर एक बड़ा सवालिया निशान है जो लगातार बढ़ रहा है। इतनी भारी सब्सिडी के बावजूद, कुल मिलाकर खाद्य आधारित मुद्रास्फीति बहुत चिंता का विषय है और एक गंभीर विचार है। एक फार्म-टू-फॉर्कश खुदरा आपूर्ति प्रणाली की अनुपस्थिति अनुपस्थित है, जो खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के मुख्य कारणों में से एक है।

एम्पायरिकल फाइंडिंग्स

भारत में कृषि खुदरा बाजार बहुत ही नुकसानदेह स्थिति में है, जो कि घरेलू और साथ ही विश्व बाजार तक पहुंचने के लिए रास्ते की कमी से पीड़ित है। यह मोटे तौर पर इस क्षेत्र की नवीनतम तकनीक तक पहुंचने और इसके मार्केटिंग इंटरफेस में सुधार करने में असमर्थता के कारण रहा है। स्वदेशी राजधानी या विदेशी पूंजी द्वारा प्रेरित संगठित खुदरा बाजार का विकास बहुत महत्वपूर्ण है जहां छोटे और सीमांत किसान इन बड़े खुदरा विक्रेताओं (भारतीय या विदेशी) को सीधे अपने उत्पाद की आपूर्ति कर सकते हैं। पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की कमी और उचित भंडारण सुविधा की कमी के कारण किसान अपने उत्पादों को बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होते हैं जो कभी-कभी उत्पादन लागत को भी कवर नहीं कर सकते हैं। अधिक उत्पादन या ग्लूट दोनों ही किसान की परेशानी का कारण बन जाते हैं। सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि 28% धान उत्पादन शून्य लाभ मार्जिन पर बेचा जाता है और धान उत्पादन लाभ मार्जिन के 45% के लिए 5 से 10 प्रतिशत तक भिन्न होता है। केवल यह कुल उत्पादन का बाकी 26% है जहां लाभ मार्जिन 10% से ऊपर है। लेकिन अधिकतम लाभ मार्जिन 15% है। मुख्य कारण भंडारण सुविधा की कमी, सरकारी तंत्र की न्यूनतम समर्थन मूल्य और संगठित विपणन बुनियादी ढांचे के आभासी गैर-अस्तित्व के साथ किसानों तक पहुंचने में विफलता है।

टेबल-1 कृषि विपणन स्कोरर

मुनाफे का अंतर	धान	गेहूँ	आलू	तिलहन	सब्जियां
0.5%	28	14	40	44	82
5.10%	46	42	52	41	14
10.15%	26	08	05	33	06

डेटा स्रोत: सर्वेक्षण

भारत में खुदरा क्षेत्र (विपणन) में एफडीआई

पिछले दो दशकों में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह के साथ-साथ रोजगार, बुनियादी ढांचे के विकास और व्यावसायिक जलवायु पर अनुकूल परिणामों के साथ वृद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। बढ़ती घरेलू उपभोक्ता बाजारों के साथ तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था ने ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में खुदरा क्षेत्र के विकास को तेज दर से बढ़ाया है।

टेबल- 2 क्रमबद्ध रिटेल की स्थिति

खुदरा क्षेत्र	अमेरिका	थाईलैंड	चीन	भारत
संगठित	85	40	20	03
असंगठित	15	60	80	97

स्रोत पी. शिवकुमार और एस सेंथिलकुमार, 2011

संगठित खुदरा में अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारी क्षमता है जो अभी भी नवजात अवस्था में है। कुल मिलाकर एफडीआई प्रवाह में खुदरा क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत कम है (0.02%), यह विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में भारत में विकास की सीमाओं को देखते हुए बहुत अधिक विकास क्षमता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अवसंरचना, संचार नेटवर्क, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, आधुनिक तकनीक आदि के बारे में वर्तमान सेटअप के साथ, पद1990 के संगठित खुदरा क्षेत्र के उदारीकरण के साथ ही कई भारतीय खिलाड़ी बढ़ गए हैं, जब कई भारतीय खिलाड़ी जैसे शॉपर्स स्टॉप, पैंटालून रिटेल इंडिया लिमिटेड, स्पेंसर रिटेल संगठित रूप से संगठित हुए। खुदरा बाजार। सिंगल ब्रांड रिटेल और कैश कैरी फॉरमेट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शुरू होने से भारतीय खुदरा बाजार को एक नई गति मिली है। 1991 में विदेश व्यापार नीति में उदारीकरण के साथ, भारत सरकार ने थोक कैश-एंड-कैरी और सिंगल ब्रांडेड रिटेलिंग में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी लेकिन, इसने खुदरा में विदेशी निवेश को प्रतिबंधित कर दिया। 1997 में रिटेल सेक्टर पर फिर से प्रतिबंध लगाए गए लेकिन 2006 में इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया और सिंगल ब्रांड रिटेलिंग और कैश-एंड कैरी फॉर्मेट में खोला गया। भारतीय रिटेल उद्योग कई वैश्विक खिलाड़ियों के लिए एक

आकर्षक एफडीआई गंतव्य बन गया है और कैरी फॉर्मेट ग्लोबल रिटेलिंग दिग्गजों के लिए प्रवेश मार्ग बन गया है। वॉलमार्ट ने भारती के साथ कैश-एंड-बिजनेस के लिए गठबंधन किया है और भारती फ्रंट-एंड-रिटेल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टेस्को भारतीय खुदरा बाजार में ट्रेंट (टाटा समूह) के साथ गठबंधन के माध्यम से प्रवेश करती है। कई विदेशी ब्रांड प्रमुख भारतीय खुदरा विक्रेताओं (जैसे लुई वुइटन, मार्क्स और स्पेन्सर पीएलसी, अरमानी) के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से या भारत में दुकानें स्थापित करने के लिए विशेष फ्रेंचाइजी के माध्यम से (जैसे मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज) में प्रवेश करते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश के साथ, परिचालन प्रारूप और मूल्य निर्धारण पर नए व्यापार मॉडल लागू करने और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और सुधार के मामले में भारतीय संगठित खुदरा बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है। रिटेल में एफडीआई के खिलाफ अक्सर तर्क दिया जाता है कि यह माँ और पॉप दुकानों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा वे प्रतिस्पर्धा से बच नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे पास पहले से ही आधुनिक रिटेलर्स जैसे बिग बाजार, नीलगिरि इत्यादि हैं जो पारंपरिक किराने की दुकानों के साथ संपन्न हैं। तो, किसी भी मामले में, हमारे पास बाजार में आधुनिक खुदरा विक्रेता हैं। भारतीय खुदरा बाजार पश्चिमी खुदरा बाजार से बहुत अलग है। भारत में उपभोक्ता अक्सर और कम मात्रा में खरीदारी करना पसंद करते हैं। अपने स्वयं के निवास स्थान से दूर बड़े खुदरा स्टोरों की यात्रा करने के बजाय, लोग अभी भी पारंपरिक पड़ोस किराना स्टोर की सुविधा को पसंद करते हैं। अधिक से अधिक किराना स्टोर नकदी और कैरी स्टोर से खरीद सकते हैं और खरीद की लागत को कम कर सकते हैं। कृषि अभी भी भारत की श्रम शक्ति का 60% हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में सुधार से उन्हें सीधे लाभ होगा। खुदरा क्षेत्र में 100% एफडीआई के कारण देश में कृषि और डेयरी क्रांति हो जाएगी।

कृषि और वृक्षारोपण में एफडीआई के संबंध में वर्तमान नीति इस प्रकार है

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100% उल्लेख के तहत गतिविधियों अर्थात में स्वत: मार्ग के तहत अनुमति दी है।, फूलों की खेती, बागवानी, बीज, पशुपालन, के विकास के मछली पालन, मत्स्य पालन और सब्जियों और मशरूम की खेती, नियंत्रित परिस्थितियों और सेवाओं के तहत कृषि से संबंधित और संबद्ध क्षेत्र।
- पांच साल की अवधि के भीतर भारतीय भागीदार/भारतीय जनता के पक्ष में कंपनी की 26% इक्विटी के विभाजन की शर्तों के अधीन चाय बागान में पूर्व सरकार की मंजूरी के साथ 100% तक की एफडीआई की अनुमति है य और किसी भी भविष्य के भूमि उपयोग परिवर्तन के मामले में संबंधित राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति।
- उपरोक्त दो के अलावा, किसी अन्य कृषि क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।
- सरकार ने कृषि क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की घोषणा की है जिसमें बीज, वृक्षारोपण, बागवानी और सब्जियों की खेती शामिल है। औद्योगिक नीति और संवर्धन (डीआईपीपी) पशुपालन, विभाग द्वारा सर्कुलर के अनुसार मछली पालन, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित नियंत्रित परिस्थितियों और सेवाओं के तहत मत्स्य पालन भी चाय क्षेत्र के साथ-साथ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100 के साथ प्रदान किया गया है।

नए नियम 1 अप्रैल, 2011 से लागू किए गए हैं। डीआईपीपी ने ट्रांसजेनिक बीज और सब्जियों के विकास से निपटने वाली कंपनियों के लिए कुछ शर्तें लागू की हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों या रोपण सामग्री से निपटने के दौरान, कंपनी को आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों के अनुसार सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने की उम्मीद है यदि आवश्यक हो, तो आनुवंशिक रूप से संशोधित सामग्रियों का कोई भी आयात, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत जारी की गई अधिसूचना के अधीन होगा।

उपसंहार

देशी या विदेशी पूंजी द्वारा निष्कर्ष पूंजी निवेश कृषि खुदरा बिक्री में निवेश के माहौल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली उत्प्रेरक लगता है, जो कि वर्तमान आपूर्ति अकुशल आपूर्ति श्रृंखला, उचित भंडारण सुविधाओं की कमी और किसानों और प्रत्यक्ष के बीच बहुस्तरीय मध्यस्थों की उपस्थिति को ध्यान में रखता है। उपभोक्ताओं कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए विपणन बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की आवश्यकता है जो कि सरकारी क्षेत्र से नहीं निकल रहा है। एफडीआई-संचालित आधुनिक रिटेलिंग किसानों और खुदरा विक्रेताओं के बीच एक सीधा इंटरफेस है जो कई प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करता है जो लंबे समय में भारत में सभी कृषि राज्यों के ग्रामीण कृषि विभाग की आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देने की नीति से विदेशी रिटेलर और भारतीय भागीदार दोनों को लाभ हो सकता है - विदेशी खिलाड़ियों को स्थानीय बाजार का ज्ञान

मिलता है, जबकि भारतीय कंपनियां वैश्विक सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं, डिजाइनों और तकनीकी जानकारियों का उपयोग कर सकती हैं। इस क्षेत्र को आंशिक रूप से खोलने से, सरकार द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में अपने व्यापारिक साझेदारों के दबाव को कम कर सकती है और चरणबद्ध तरीके से इस क्षेत्र को उदार बनाने में भारत के इरादों को प्रदर्शित कर सकती है। कृषि खुदरा बिक्री में विदेशी निवेश की अनुमति देना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने की संभावना है, जिससे समाज के सभी वर्गों, विशेषकर किसानों और उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। यह किसान आय और कृषि विकास में सुधार लाएगा और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को कम करने में सहायता करेगा। इसके अलावा, खुदरा व्यापार में एफडीआई की अनुमति देकर, भारत गुणवत्ता के मानकों और उपभोक्ता अपेक्षाओं के मामले में महत्वपूर्ण रूप से फल-फूल जाएगा, क्योंकि खुदरा क्षेत्र मंष एफडीआई की आमद गुणवत्ता मानकों और भारतीय किसानों की लागत प्रतिस्पर्धा को खींचने के लिए बाध्य है। इसलिए, ऐसा लगता है कि कृषि खुदरा बिक्री में एफडीआई में कृषि विकास को बनाए रखने की क्षमता है। यह ध्यान दिया जाना है कि भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद (ICRIER), देश का एक प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक, जिसे खुदरा क्षेत्र में BIG पूंजी के प्रभाव को देखने के लिए नियुक्त किया गया था, ने भारतीय मूल्य का अनुमान लगाया है खुदरा क्षेत्र 2011-12 तक 496 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और आईसीआरआईआर भी निष्कर्ष पर आया है कि खुदरा क्षेत्र में पैसा (बड़े कॉर्पोरेट और एफडीआई) का निवेश भविष्य के बाजार को ध्यान में रखते हुए छोटे और पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उपरोक्त के प्रकाश में, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खुदरा क्षेत्र में स्वस्थ एफडीआई की अनुमति देने से न केवल देश की जीडीपी और समग्र आर्थिक विकास में पर्याप्त वृद्धि होगी, बल्कि इससे भारतीय कृषि खुदरा बाजार को एकीकृत करने में भी मदद मिलेगी। वैश्विक खुदरा बाजार भारतीय किसानों को उच्च लाभ मार्जिन प्रदान करने के अलावा, जो असंगठित क्षेत्र निस्संदेह प्रदान करने में विफल रहा है। CII FICCI US & India Business Council USIBC अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) और शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (भारतीय मल्टी-ब्रांड रिटेलर्स का 44 सदस्यीय संघ) जैसे औद्योगिक संगठन और शॉपिंग मॉल) मल्टी-ब्रांड रिटेलिंग में एफडीआई को उदार बनाने की दिशा में एक चरणबद्ध दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, और उनमें से अधिकांश 49-51 प्रतिशत की कैप पर विचार करने के लिए सहमत हैं। कृषि खुदरा बिक्री में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सावधानी से निपटाया जाना चाहिए क्योंकि इसका आबादी के बड़े हिस्से पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वाम अकेला विदेशी पूंजी तरीके है, जो यह केवल गुणा ही कर सकते हैं, और लाभ के लिए राजधानी के कल्पनातीत आवेदन के माध्यम से हमारे अजीब सामाजिक दी तलाश करेंगे आर्थिक स्थितियां, कयामत वर्तनी और अमीर और गरीब के बीच की खाई को गहरा कर सकते हैं। इस प्रकार कृषि खुदरा बिक्री में विदेशी पूंजी के प्रसार को इस तरह से लंगर डाले जाने की जरूरत है कि यह भारत के लिए एक जीत की स्थिति पैदा करे। यह जानबूझकर कुछ इनबिल्ट सेफ्टी वाल्व लगाकर एफडीआई रिटेलिंग के लिए नियमों और विनियमों को एकीकृत करके किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी निवेशक बुनियादी ढांचे और रसद के विकास में वास्तविक योगदान देते हैं, यह निर्धारित किया जा सकता है कि एफडीआई का एक प्रतिशत बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स या कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण की ओर खर्च किया जाना चाहिए। गरीबी से त्रस्त और ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ने और समृद्ध ग्रामीण क्षेत्र में पुनर्गठित करने से कृषि खुदरा बिक्री में एफडीआई शुरू करने के औचित्य में से एक हो सकता है लेकिन सरकार को एक विशेष नियामक ढांचा तैयार करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि रिटेलिंग दिग्गज शिकारी मूल्य निर्धारण का सहारा न लें या एकाधिकारवादी प्रवृत्ति प्राप्त न करें। इस प्रकार, भारतीय खुदरा क्षेत्र में चर्चा के दौरान FDI के तथ्य के रूप में न केवल स्वतंत्र रूप से अनुमति दी जानी चाहिए, बल्कि प्रति गर्भधारण को काफी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की आपूर्ति आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, प्रौद्योगिकी में निवेश, जनशक्ति और कौशल विकास, पर्यटन विकास, भारत से अधिक से अधिक सोर्सिंग, कृषि में उन्नयन, कुशल लघु और मध्यम उद्योगों, बाजार के आकार में वृद्धि और सरकार को लाभ प्रदान कर सकती है। अधिक से अधिक जीडीपी, कर आय और रोजगार सृजन के माध्यम से।

संदर्भ

1. ओमारी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में रिटेलिंग का आयोजन जर्नल ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, 6 (1) 651-2998
2. के खत्री, रिटेल इंडस्ट्री की भविष्य की संभावनाएं यूरोपीय जर्नल ऑफ मार्केटिंग, 41 (11) 2007
3. डी। गुप्ता, 'व्हेयर द इंडियन विलेज,' इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, फरवरी 2005।

4. एस चैधरी, फार्म फैटलिटीज द स्टेट्समैन, फरवरी 6, 2012

5. पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल मानव विकास रिपोर्ट, 2004

6. पी। शिवकुमार और एस सेंथिलकुमार, 'ग्रोइंग प्रॉस्पेक्टिव ऑफ रिटेलइंड्रॉयड और भारत के आसपासश्, एडवांसमेंट इन मैनेजमेंट, वॉल्यूम 4 (2), 2011

7. आर्थिक सुधार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और भारत में इसके आर्थिक प्रभाव से चांदना चक्रबोर्ती पीटर मार्च 2006

8. हारून, सी, (1999), 'गरीबी उन्मूलन में एफडीआई का योगदान: रिपोर्ट, विदेशी सलाहकार सेवा।'

9. बुर्फीशेर, मैरी, शेर्मन रॉबिंसन और करें थिएरफेल्डर (1992), 'संयुक्त राज्य अमेरिका-मेक्सिको मुक्त व्यापार क्षेत्र में कृषि और खाद्य नीतियां,' नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, वॉल्यूम. 3 नंबर 2, पीपी. 17-39।

10. चिरावुरी सृजना (2014), 'भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव की तीसरी विजेता अग्रसक्रिप्टुम पेशेवर श्रेणी के अंतर्गत।

11. हुड्डा, एस (2011), "एफडीआई और भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन, ऑनलाइन प्रकाशन, पीपी। 114-115। उपलब्ध है: http://www-nitkkr-ac-in/Spna_Hooda।

12. कपिल सिंह रितु के वालिया (2015), ष्विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और भारत में कृषि क्षेत्र परिपेक्ष - इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च, टवस। 4, अंक, 3, आईएसएसएन, 2250-1991।

Corresponding Author

Dr. Nitin Bhardwaj*

Lecturer (Economics), S.L. Education Institute, Moradabad